भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 415

दिनांक 22 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र के जलगाँव में डेयरी फार्मिंगए

415. श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश भर में पांच एकड़ तक की भूमि वाले ग्रामीण किसानों के लिए छोटे पैमाने के डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) 5 से 10 जानवरों के लिए डेयरी इकाइयों के लिए किस प्रकार की सहायता और योजनाएं उपलब्ध हैं और ये योजनाएँ छोटे और सीमांत किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचा रही हैं;

(ग) विगत पाँच वर्षों में इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले किसानों की, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य और जलगांव निर्वाचन क्षेत्र सहित, राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास जलगांव में छोटे डेयरी फार्मिंग को सुदृढ़ करने की कोई विशेष योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन किसानों को सहायता कब प्रदान की जाएगी;

(ङ) यदि हाँ, तो जलगांव में इस प्रकार की योजना की शुरुआत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार के पास इस क्षेत्र में ग्रामीण डेयरी किसानों की इस दीर्घकालिक मांग को पूरा करने की कोई योजना है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (च): छोटे पैमाने पर डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है और निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि दूध की बढ़ती माँग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभदायक बनाने हेतु बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों सहित डेयरी किसानों को उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP): इस घटक के अंतर्गत 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में किसानों के घर पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं । वर्तमान में एनएआईपी महाराष्ट्र के 33 जिलों में कार्यान्वित है और अब तक, 56.57 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 76.73 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 36.60 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। महाराष्ट्र के जलगाँव

जिले में, एनएआईपी के तहत 1.87 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 2.41 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 1.25 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ii) देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए संतति परीक्षण और नस्ल चयन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। महाराष्ट्र की गोपशु की गाओलाओ नस्ल और भैंस की पंढरपुरी नस्ल इस कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं;

(iii) बोवाइन आबादी में तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए आईवीएफ तकनीकी और सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 2 आईवीएफ प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं और इन प्रयोगशालाओं का लाभ महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित राज्य के सभी डेयरी किसानों को मिल रहा है।

(iv) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (MAITRIs) को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है। महाराष्ट्र में कुल 853 मैत्री प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं, जिनमें महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में नियुक्त 30 मैत्री शामिल हैं;

(v) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के घटक के तहत विभाग ने जलगांव जिले के लिए संस्वीकृत 1 बीएमएफ सहित 33 नस्ल वृद्धि फार्मों को अनुमोदित किया है।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है: (i) एनपीडीडी का घटक "क" राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ/स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है और (ii) एनपीडीडी योजना के घटक "ख" "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत जलगांव जिले सहित महाराष्ट्र राज्य में 5177.21 लाख रुपये के कुल परिव्यय वाली 4 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

3. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) को पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है । महाराष्ट्र राज्य में इस योजना के तहत अब तक खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) के लिए 10.25 करोड़, ब्रुसेलोसिस के लिए 28.01 लाख, पीपीआर के लिए 2.35 करोड़ और क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) के लिए 1.58 लाख टीकाकरण किए गए हैं। जलगाँव जिले में अब तक एफएमडी के लिए 41.62 लाख, ब्रुसेलोसिस के लिए 1.07 लाख, पीपीआर के लिए 9.13 लाख और सीएसएफ के लिए 0.07 लाख टीकाकरण किए गए हैं। राज्य में कुल 80 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (MVU) चालू हैं, जिनमें जलगाँव जिले में 5 MVU चालू हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देशभर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना के अंतर्गत नया घटक पशु औषधि जोड़ा गया है। इससे किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

4. भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा का विस्तार किया है, जिसमें स्वामित्व वाले/किराए पर/पट्टे पर शेड वाले किरायेदार किसान सहित किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह इस योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं और अब तक महाराष्ट्र में पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए 1,10,358 नए केसीसी जारी किए गए हैं।

5. भारत सरकार डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना की स्थापना सहित पशुधन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु 29,110.25 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान कर रही है। यह अनुदान अधिकतम 8 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएआईपी (NAIP) के तहत समर्थित किसानों की संख्या का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है तथा महाराष्ट्र में एएचआईडीएफ (AHIDF) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

***

अनुबंध- I

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम		
		कवर किए गए पशु	किए गए एआई (AI)	लाभान्वित किसान
1	आंध्र प्रदेश	7271593	13534121	3385494
2	अरुणाचल प्रदेश	3896	4553	1808
3	असम	1728956	2259202	1469462
4	बिहार	3939394	5426332	2699120
5	छत्तीसगढ	1899186	2555961	1136298
6	गोवा	25869	43346	8741
7	गुजरात	5851560	9414998	3472009
8	हरियाणा	616051	888738	447974
9	हिमाचल प्रदेश	1826836	2984525	1333501
10	जम्मू और कश्मीर	2378443	4258437	1610132
11	झारखंड	2687916	3606125	1820869
12	कर्नाटक	8316189	16365745	5213640
13	लद्दाख	7409	9374	6049
14	मध्य प्रदेश	7897299	9691938	4677115
15	महाराष्ट्र	5657630	7673491	3660588
16	मणिपुर	27786	32608	16248
17	मेघालय	51326	85953	16630
18	मिजोरम	8712	12650	3989
19	नागालैंड	41209	53282	16966
20	ओडिशा	4918641	6635012	3074382
21	पंजाब	1195739	1896192	636970
22	राजस्थान	5952426	7869493	4138417
23	सिक्किम	43868	54931	33777
24	तमिलनाडु	5043636	8532152	2338501
25	तेलंगाना	3244563	4237569	1665755
26	त्रिपुरा	248420	333665	209181
27	उत्तर प्रदेश	14015463	22167599	7892528
28	उत्तराखंड	1511187	2447353	1064152
29	पश्चिम बंगाल	5218518	8166218	3437398
कुल		**91629721**	**141241563**	**55487694**

अनुबंध- II

महाराष्ट्र में एएचआईडीएफ (AHIDF) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनुमोदित परियोजनाएं (संख्या)	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1	अहमदनगर	1	69.62
2	औरंगाबाद	2	117.04
3	धुले	2	4.63
4	नासिक	4	43.2
5	पुणे	3	40.33
6	सोलापुर	2	8.54